उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा

4506. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा दम तोड़ रही है और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इसके कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं;

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश के कितने माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, सरकार ने इस शिक्षा के लिए सबसे पहले कब और कितने विद्यालयों का चयन किया था, तत्संबंधी वर्ष-वार और विद्यालय वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) पूरे देश, विशेषकर, उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा/विद्यालयों पर प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है और विद्यालयों में चरण-वार अध्ययन की क्या प्रणाली है और क्या अब तक उनके परिणाम संतोषजनक रहे हैं, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस दिशा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (छ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में व्यावसायिक शिक्षा को दी गई प्राथमिकता के अनुसरण में फरवरी, 1988 से स्कूलों में +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। योजना को योजना के नियमों के अनुसार हिस्सेदारी की पद्धति पर केंद्रीय सरकार वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 1987-88 से वर्ष 1992-93 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए योजना के अंतर्गत 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निम्नलिखित राशियां प्रदान की गई :

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1987-88	3226.00
1988-89	4973.00
1989-90	4397.00
1990-91	7480.00
1991-92	5689.00
1992-93	7752.00
कुल :	33438.00

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों

को शुरू करने के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित राशियां प्रदान की गई

वर्ष	राशि	संस्वीकृत व्यावसायिक पैकेजों की संख्या	शामिल किये गये स्कूलों की संख्या
1987-88	829.88	800	200
1988-89	800.00	450	150
1989-90	203.69	—	—
1990-91	707.25	500	260
1991-92	99.14	—	—
1992-93	581.39	200	100
	3221.357	1950	710

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार अब तक 1156 पैकेजों सहित 460 स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए है।

केंद्रीय सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (शिक्षा विभाग जो अब सी. आई. बी. ई. है) +2 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते रहे हैं। कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की जाती हैं और शैक्षिक सहायता सहित सभी संभव सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारें को ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करते हुए कार्यक्रम में सुधार के लिए सघटित प्रयास करना चाहिए जिनके लिए निधियां प्रदान की गई हैं ताकि कार्यक्रम को उचित रूप से संस्थागत बनाया जा सके।

Shortlisting Criteria for P.G. Teachers in KVs.

4506 SHRI NARAIN PRASAD GUPTA:
SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the short-listing criteria for the post of post Graduate Teachers of Kendriya Vidyalayas is being/has been changed; and

(b) if so, the details and justification thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) Kendriya Vidyalaya Sangathan has decided to short-list eligible candidates for interview based on the academic achievements in Higher Secondary, Graduation, Post Graduation and teaching degree/diploma so as to provide for objectivity, equality of opportunity for meritorious teachers and the need for competent subject teachers in the grade of Post Graduate Teacher.

The ratio for calling candidates for interview has been fixed as 1:8.

Meeting of U.G.C.

4507 SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the University Grants Commission (UGC) in its meeting held in July, has taken any decision in regard to three major issues viz resource crunch; payment receipts and reemployment of teachers;

(b) if so, what are the main reasons for delay in taking decision in this regard;